

कर्नाटक चुनाव में 375 करोड़ रुपये जब्त किए गए, 2018 की तुलना में 4.5 गुना अधिक : ईसीआई

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को कहा कि 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 375 करोड़ रुपये की जब्ती की गई, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दक्षिणी राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 288 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। चुनाव आयोग ने यह खुलासा 8 मई को प्रचार समाप्त होने के एक दिन बाद किया। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना है और मतों की गिनती 13 मई को होगी। पोल पैनल के अनुसार, पिछले कुछ चुनावों से श्रमलोभन–मुक्त चुनावों पर इसका जोर जारी रहा है और कर्नाटक के चुनाव वाले राज्य में चुनाव खर्च की निगरानी के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में राज्य में रिकॉर्ड की गई बरामदगी में 4.5 गुना की वृद्धि हुई है। इसने बताया कि कड़ी निगरानी, व्यापक निगरानी, पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय और अंतर–यूजेंसी समन्वय ने इस बार कर्नाटक में चेकिंग फ्लो और डिस्ट्रीब्यूशन की जांच की है। पोल पैनल ने कहा कि उसने 147.46 करोड़ रुपये की नकदी और 83.66 करोड़ रुपये की शराब जब्त की है।इसने



आगे कहा कि ड्रग्स की कीमत 23.6 करोड़ रुपये, कीमती धातुएं 96.6 करोड़ रुपये और 24.21 करोड़ रुपये की मुफ्त चीजें हैं। चुनाव आयोग ने कहा, २023 में, उसने कुल 375 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की, जो 2018 के विधानसभा चुनावों में 83.93 करोड़ रुपये की तुलना में 4.5 गुना अधिक है। इसने कहा कि इसके अतिरिक्त, मार्च, 2023 के दूसरे सप्ताह में आयोग के दौरे की तारीख से चुनाव की घोषणा की तारीख तक, चुनाव वाले राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 83.78 करोड़ रुपये की जब्ती भी की गई।

चुनाव आयोग ने कहा, ईडी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 288 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की है। इसने यह भी कहा कि उल्लेखनीय बरामदगी में कोलार जिले के बंगारापेट एसी में 4.04 करोड़ रुपये की नकदी की जब्ती, हैदराबाद में अवैध रूप से अल्ट्राजोलम बनाने वाली लैब पर छापा मारना और एनसीबी द्वारा की गई ट्रेल मैपिंग, बीदर जिले में जब्त 100 किलोग्राम गांजा सहित सभी जिलों से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। व्यय निगरानी की एक और उल्लेखनीय विशेषता मुफ्त उपहारों की

भारी जब्ती रही है। कलबुर्गी, चिकमंगलूर और अन्य जिलों से साड़ियां और खाने के किट जब्त किए गए हैं। बैलहोंगल और कुनिगल और अन्य एसी से भारी मात्रा में प्रेशर कुकर और रसोई के उपकरण भी जब्त किए गए। पैनल ने 146 व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात किया था और 81 विधानसभा क्षेत्रों को कड़ी निगरानी के लिए व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया था।आयोग ने 1 मई को कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सीमा चौकियों के माध्यम से कानून और व्यवस्था की स्थिति और अंतर–राज्य चौकरी की भी समीक्षा की थी। समीक्षा में इन सभी सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिवों, डीजीपी, आबकारी आयुक्तों और प्रमुख प्रवर्तन एजेंसियों के क्षेत्रीय प्रमुखों ने भाग लिया। इस अवसर पर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सीमावर्ती जिलों में विशेष रूप से 185 चेक पोस्टों की उचित मैनिंग और निगरानी पर जोर दिया था।आयोग ने कहा कि इस तरह की सीमा चौकियों से नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु और मुफ्त सामान की जब्ती बांटे में 70 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।

महरोली हत्याकांड: दिल्ली की अदालत ने पूनावाला के खिलाफ आरोप तय किए

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने महरोली हत्याकांड में अपनी लिव–इन पार्टनर श्रद्धा वालकर का गला घोटने और फिर उसके शव के कई टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय किए। साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की ६11A 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत आरोप तय किए हैं। एएसजे खुराना ने कहा, प्रथम दृष्ट्या धारा 302 का मामला बनता है और आरोप तय किए जाएंगे।न्यायाधीश ने कहा कि खुद को सजा से बचाने के लिए, पूनावाला ने वालकर के शरीर को काट दिया और इसे विभिन्न जगहों पर फेंक दिया, इसलिए यह आईपीसी की धारा 201 के तहत भी अपराध है। पूनावाला ने वालकर की हत्या के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मामले को अब सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख तय की गई है जब लिए अजमेर से जयपुर तक अपनी के जन संघर्ष पदयात्रा शुरू करेंगे।

कि उनके बयान के क्या मायने हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वसुंधरा राजे उनकी सरकार बचाने की कोशिश कर रही थीं। वो कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह 11 मई को भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर करने और राज्य के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए अजमेर से जयपुर तक अपनी के जन संघर्ष पदयात्रा शुरू करेंगे।

है कि कैसे मोली–भाली लड़कियों को बरगलाया जाता है और फिर उनका ६11A तर्पण किया जाता है। विपुल अमृत शाह द्वारा निर्मित, सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और अदा शर्मा अभिनीत फिल्म थिएटर बुक किया और कहा कि युवा लड़कियों को कथित लव जिहाद से बचाने के लिए फिल्म दिखाई जानी चाहिए। मिश्रा ने कहा कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और दिखाती

पायलट-गहलोत लड़ाई पर जल्द होगी दिल्ली में कांग्रेस की बैठक

नई दिल्ली। राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलट के मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फिर आलोचना करने के बाद पार्टी के राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली में राज्य के नेताओं की एक बैठक बुलाने का फैसला किया है। सूत्रों से ये जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही बैठक की तारीख फाइनल की जाएगी। सूत्र ने कहा कि रंधावा राजस्थान संकट पर चर्चा के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कर्नाटक से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सूत्र ने यह भी कहा कि रंधावा ने राजस्थान के वरिष्ठ नेतृत्व और सभी महासचिवों और सचिवों को दिल्ली की बैठक में शामिल होने के लिए कहा है। बैठक आयोजित करने का फैसला तब आया जब पायलट ने जयपुर में गहलोत के खिलाफ तीखा हमला किया। संयोग से, राहुल गांधी भी राजस्थान में हैं। जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा, परसों धौलपुर में मुख्यमंत्री के भाषण से यह बात



साफ हो गई है। पायलट ने गहलोत के उस बयान पर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेताओं की तारीफ की थी, लेकिन पार्टी के अपने ही सांसदों और विधायकों की छवि खराब की। रविवार को गहलोत ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा के दो नेता कैलाश मेघवाल और शोभरानी कुशवाहा ने उनकी सरकार को बचाने में मदद की थी। गहलोत के बयान पर पायलट ने कहा, गहलोत बताएं

कि उनके बयान के क्या मायने हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वसुंधरा राजे उनकी सरकार बचाने की कोशिश कर रही थीं। वो कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह 11 मई को भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर करने और राज्य के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए अजमेर से जयपुर तक अपनी

द केरला स्टोरी से प्रतिबंध हटाकर जनता को सच देखने दें प.बंगाल और तमिलनाडु की सरकारें : केशव प्रसाद मोर्य

भदोही। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्य ने विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की निंदा करते हुए मंगलवार को इन सरकारों से कहा कि वे तत्काल प्रतिबंध हटाएं और जनता को सच देखने दें। उपमुख्यमंत्री ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में फिल्म द केरला स्टोरी पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार द्वारा पाबंदी लगाए जाने से संबंधित सवाल पर कहा कि इन सरकारों का यह कदम निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारें इस फिल्म पर लगी पाबंदी को हटा लें ताकि जनता सच देख सके। मोर्य ने कहा, जहां–जहां भाजपा की सरकार है वहां इस फिल्म को कर मुक्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसे सरकार ने कर मुक्त कर दिया है। उपमुख्यमंत्री ने चुनावी सभा में कहा कि निकाय चुनाव के बाद हर नगर पालिका और नगर पंचायत



विकास का जो भी प्रस्ताव बनाकर भेजेगी, उन्हें राज्य सरकार जरूर पूरा करेगी। गौरतलब है कि गत पांच मई को रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत पांच मई को इस फिल्म को आतंकी साजिशों को सामने लाने का श्रेय दिया था। उन्होंने कर्नाटक में एक चुनावी रैली में फिल्म का उल्लेख करते हुए कांग्रेस

पर निशाना साधा था। उत्तर प्रदेश भाजपा के सचिव अभिजात मिश्रा ने शनिवार को शहर में करीब 100 छात्राओं के लिए इस विवादित फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। उन्होंने एक थिएटर बुक किया और कहा कि युवा लड़कियों को कथित लव जिहाद से बचाने के लिए फिल्म दिखाई जानी चाहिए। मिश्रा ने कहा कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और दिखाती

है कि कैसे मोली–भाली लड़कियों को बरगलाया जाता है और फिर उनका ६11A तर्पण किया जाता है। विपुल अमृत शाह द्वारा निर्मित, सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और अदा शर्मा अभिनीत फिल्म थिएटर बुक किया और कहा कि युवा लड़कियों को कथित लव जिहाद से बचाने के लिए फिल्म दिखाई जानी चाहिए। मिश्रा ने कहा कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और दिखाती

नाव हादसे को लेकर भाजपा ने केरल के पर्यटन मंत्री का इस्तीफा मांगा

तिरुवनंतपुरम। केरल भाजपा ने तनूर नाव हादसे में गंभीर चूक का आरोप लगाते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास का इस्तीफा मांगा है। राज्य भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने कहा कि 2009 में हुई तैक्कडी त्रासदी के बाद कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई जिसमें एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन पर 45 लोग डूब गए थे, जिनमें ज्यादातर दूसरे राज्यों के थे। सुरेंद्रन ने दावा किया कि अगर तैक्कडी त्रासदी की रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की गई होती तो तनूर त्रासदी को टाला जा सकता था। भाजपा नेता ने कहा, रियास को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना होगा।

अगर उचित कार्रवाई की जाती तो 22 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। केरल में केवल बयानबाजी और विज्ञापन ही होते हैंकू हाउसबोट के संचालन के लिए कोई प्रभावी दिशा–निर्देश नहीं हैंकू किसी को नहीं मालूम कि केरल में कितने हाउसबोट हैं या उनका कोई प्रभावी निगरानी की जा रही है या नहीं।सुरेंद्रन ने कहा, ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि सुरक्षा में किसी की दिलचस्पी नहीं है। हम उचित जांच और जांच के आधार पर कार्रवाई की मांग करते हैं।

मणिपुर हिंसा: 1700 घरों को जलाया गया, सेना की कड़ी निगरानी, 11 जिलों में दी गई कर्फ्यू में ढील

इंफाल। हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थिति में सुधार हो रहा है तथा किसी भी अभिय घटना की कोई ताजा खबर नहीं है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि जिन 11 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया था वहां भी इसमें ढील दी गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि पिछले कुछ दिन में पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा में 60 लोगों की मौत हो गई और 231 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि इस हिंसा के दौरान मंदिरों तथा गिरजाघरों समेत 1,700 इमारत और मकान जला दिये गये। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “पूरे राज्य में स्थिति में सुधार हो रहा है, पिछले 24 घंटों में हिंसा की कोई खबर नहीं हैकू इंफाल पश्चिम और इंफाल पूर्व में आज सुबह पांच बजे से चार घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। अन्य नौ प्रभावित जिलों में फैंल गई इसी तरह की छूट दी जा रही है।” मणिपुर में बहुसंख्यक मेइती समुदाय द्वारा उसे अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में ‘ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुरर (एटीएसयूएम) की ओर से तीन मई



को आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के दौरान चुराचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी, जो रातोंरात पूरे राज्य में फैल गई थी। पूर्व में आरक्षित वन भूमि से कुकी ग्रामीणों को बेदखल करने पर उत्पन्न तनाव के चलते झड़पें हुईं, जिसके कारण कई छोटे–छोटे प्रदर्शन हुए। मणिपुर की कुल आबादी में मेइती समुदाय की 53 प्रतिशत हिस्सेदारी (एटीएसयूएम) की ओर से तीन मई

लोग मुख्यतः इंफाल घाटी में रहते हैं। वहीं, नगा और कुकी सहित अन्य आदिवासी समुदायों की आबादी 40 प्रतिशत के करीब है तथा वे मुख्यतः इंफाल घाटी के आसपास स्थित पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार शाम को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने मृतकों के परिवार को पांच–पांच लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को दो–दो लाख रुपए तथा

केंद्र की सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मणिपुर की हालिया हिंसा को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की एक टिप्पणी से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए कहा, “प्रधान न्यायाधीश ने जो कहा है उसके परिप्रेक्ष्य में मणिपुर उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जो किया है, वह आश्चर्यजनक है। रमेश ने कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।उन्होंने जो खबर साझा की है उसके मुताबिक, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा है कि उच्च न्यायालय को अनुसूचित जनजाति की सूची में बदलाव करने के लिए निर्देश देने का अधिकार नहीं है। मणिपुर में बहुसंख्यक मेइती समुदाय द्वारा उसे अनुसूचित

जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में ‘ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर (एटीएसयूएम) की ओर से तीन मई को आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के दौरान चुराचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी, जो रातोंरात पूरे राज्य में फैल गई थी। मणिपुर की कुल आबादी में मेइती समुदाय की 53 प्रतिशत हिस्सेदारी होने का अनुमान है। इस समुदाय के लोग मुख्यतः इंफाल घाटी में रहते हैं। वहीं, नगा और कुकी सहित अन्य आदिवासी समुदायों की आबादी 40 प्रतिशत के करीब है तथा

वे मुख्यतः इंफाल घाटी के आसपास स्थित पहाड़ी जिलों में रहते हैं। हिंसा के कारण 50 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा 23,000 लोगों ने सैन्य छावनियों और राहत शिविरों में शरण ले रखी है। उल्लेखनीय है कि जनजातीय लोग 27 मार्च को मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मेइती समुदाय को आरक्षण दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार को चार हफ्तों के अंदर केंद्र को एक सिफारिश भेजने का निर्देश दिया था।



मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, “ये बहुत–बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं।” में लोगों से जल्द से जल्द शांति का माहौल बनाने की अपील करता हूं। सिंह ने बताया कि हिंसा के दौरान मंदिरों तथा गिरजाघरों समेत 1,700 इमारत और मकान जला दिए गए। उन्होंने कहा कि उन लोगों को दो–दो लाख रुपए दिए जाएंगे जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सिंह ने कहा, “मणिपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद राहत शिविरों में फंसे 20,000 से अधिक लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। 10,000 और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगाकू। मानव जीवन अनमोल है और घरों और संपत्तियों को नष्ट करना अस्वीकार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षाबल के कर्मियों से 1,041 बंदक लूटी गई जिनमें से 214 बरामद कर ली गई हैं। सिंह ने कहा कि सरकार ने चुराचांदपुर, उखरुल, इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व और कांगपोकपी जिलों के फंसे लोगों को वापस लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सिंह ने कहा, “पुलिस अधीक्षकों” को संवेदनशील इलाकों की पहचान करने तथा मालिकों की अनुपस्थिति में भूमि और संपत्ति की चौबीसों घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें लूट या ऐसी जमीन और संपत्ति पर कब्जा जमाने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।



नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के संबंध में दिए गए बयान के बारे में अदालत को सूचित किए जाने के बाद सार्वजनिक बयान नहीं दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधि त्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए एक बयान का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि अदालत इस तरह के राजनीतिकरण की अनुमति नहीं दे सकती, जब हम मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, जब मामला विचाराधीन है और शीर्ष अदालत के समक्ष है तो इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि कोई भी धर्म–आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। कथित तौर पर गश्ह मंत्री ने मुस्लिम आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया है। मेहता ने इस तरह के एक बयान के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। दवे ने तर्क दिया कि वह अदालत के समक्ष मंत्री के बयान को रिकॉर्ड पर ला सकते हैं। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत का

राजनीती से कोई लेना–देना नहीं है और इस पर सार्वजनिक बयान नहीं दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मेहता का बयान दर्ज किया कि मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण खत्म करने के राज्य सरकार के 27 मार्च के फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।दलीलों के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी। याचिकाकर्ताओं, जिन्हें एल गुलाम रसूल और अन्य शामिल हैं, ने तर्क दिया है कि ईरब्ल्यूएस लिस्ट में मुस्लिम समुदाय को शामिल करना गैरकानूनी है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।

प्रतिशत ओबीसी कोटे को खत्म करने और इस पर सार्वजनिक बयान नहीं दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मेहता का बयान दर्ज किया कि मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण खत्म करने के राज्य सरकार के 27 मार्च के फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।दलीलों के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी। याचिकाकर्ताओं, जिन्हें एल गुलाम रसूल और अन्य शामिल हैं, ने तर्क दिया है कि ईरब्ल्यूएस लिस्ट में मुस्लिम समुदाय को शामिल करना गैरकानूनी है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।

सम्पादकीय

स्त्री-शक्ति की झांकी

ऐसे वक्त में जब भारतीय महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के नये आयाम स्थापित कर रही हैं, उन्हें गरिमा के साथ उनका जायज हक दिया जाना भी उतना ही जरूरी है। हाल के दिनों में रक्षा सेनाओं में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी लोकतंत्र में महिलाओं की सशक्त होती स्थिति को ही दर्शाती है। निस्संदेह, इस दिशा में राजनीतिक नेतृत्व की उदासीनता के चलते समय–समय पर देश के शीर्ष न्यायालय ने इस फैंसले के क्रियान्वयन में रचनात्मक भूमिका का निर्वहन ही किया है। इसी क्रम में अच्छी खबर यह आयी है कि वर्ष 2024 में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में महिलाएं बड़ी संख्या में दस्तों का नेतृत्व करेंगी। यानी कर्तव्य पथ पर नारी सशक्तीकरण की झांकी को तरजीह दी जायेगी। बताया जा रहा है कि कर्तव्य पथ पर होने वाले आधिकारिक समारोह में शामिल होने वाली टुकड़ियों व बैंड दस्तों में शामिल सभी प्रतिभागी महिलाएं हो सकती हैं। अगले साल होने वाली परेड की योजना के बाबत रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को कार्यालयी ज्ञापन भेजा था। उस ज्ञापन में इस तरह की योजना का विस्तृत जिक्र किया गया था। उल्लेखनीय है कि फरवरी में रक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया था कि अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में शामिल मार्चिंग टुकड़ियों, बैंड तथा झांकियों में केवल महिला प्रतिभागी होंगी। यह सुखद ही है कि बीते सालों में गणतंत्र दिवस पर दिखायी जाने वाली झांकियों में महिला प्रतिभागियों की उपस्थिति में अपेक्षित सुधार देखा गया है। जिसमें महिला अधिकारी सेना व सुरक्षा बलों की टुकड़ियों का बखूबी नेतृत्व करती नजर आई हैं। निस्संदेह, यह प्रयास देश में आभी दुनिया को पूरे हक देने की दिशा में सार्थक पहल ही कही जा सकती है। विश्वास किया जाना चाहिए कि सरकार का हालिया निर्णय इस स्थिति को अधिक सम्मानजनक बनाने में सहायक ही साबित होगा। निस्संदेह, सरकार व रक्षा मंत्रालय की इस हालिया पहल का प्रतीकात्मक महत्व है। लेकिन महिलाओं के जीवन में असली सुधार तब आएगा जब उन्हें दिये जा रहे अधिकार जमीनी हकीकत भी बनें। हाल के दिनों में कुछ अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों को खेल संघ के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिये सड़कों पर उतरने का जो परिदृश्य नजर आया, वह स्थिति देश के विभिन्न विभागों व सेवाओं में नजर नहीं आनी चाहिए। कमोबेश सभी विभागों में महिलाओं के अधिकार और उनकी अस्मिता की रक्षा के लिये निष्पक्ष व पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारों की तरफ से आभी दुनिया को उनके हक दिलाने व कार्य परिस्थितियों को गरिमामय बनाने के लिये पारदर्शी व्यवस्था बनायी जानी चाहिए। ताकि वे बेखोफ होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। हम पहले ही महिलाओं को उनके वाजिब हक देने में बहुत देर कर चुके हैं। देश की श्रम शक्ति में चीन व अन्य विकसित देशों के मुकाबले महिलाओं की भूमिका बेहद उपेक्षित रही है। इस दिशा में गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि महिला श्रम शक्ति का देश के विकास में बेहतर ढंग से उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। दरअसल, महिला सशक्तीकरण के साथ उनकी आर्थिक आजादी भी जरूरी है। आर्थिक आजादी से उनकी निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। इससे ही महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू व सामाजिक हिंसा में कमी आएगी। घर–परिवार व बाहर संभालने वाली महिला को जब पूरी तरह से आर्थिक आजादी मिल जायेगी, उस दिन देश में लैंगिक भेदभाव समाप्त करने की दिशा में बड़ी पहल हो सकेगी। वहीं दूसरी ओर संसद में महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिये दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दर्शाने की भी जरूरत है ताकि देश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में बदलावकारी पहल हो सके। इस मामले में राजनीतिक दलों को अपने भेदभाव ताक पर रखकर इस दिशा में गंभीर पहल करनी होगी। तभी आभी दुनिया को भारतीय समाज में बराबरी का सम्मानजनक दर्जा मिल पायेगा।

भटके विमर्श का नतीजा

इस सारे विवाद की जड़ में पहचान की राजनीति और उस सियासत से जुड़े फायदे हैं। लेकिन ऐसी राजनीति में विभिन्न समुदायों के बीच टकराव खड़ा होना लाजिमी होता है। मणिपुर में वैसा ही टकराव देखने को मिला है। मणिपुर की घटनाओं ने आखिरकार पूरे देश का ध्यान खींचा है। वैसे तो मणिपुर पूरे अप्रैल में सुलगता रहा, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया ने उसकी खबर नहीं ली। जब बीते हफ्ते वहां हिंसा की आग भड़क उठी, तब सबका ध्यान आकर्षित हुआ। जबकि वहां जो हिंसा देखने को मिली है, उसकी जड़ तो मार्च में ही पड़ चुकी थी। राज्य के बहुसंख्यक मैतेयी और आदिवासी समुदाय के बीच तनाव की जड़ें पुरानी हैं। मार्च में हा ईकोर्ट के एक फैसले ने इस तनाव को और बढ़ा दिया। गैर–आदिवासी मैतेयी समुदाय की आबादी राज्य में करीब 53 फीसदी है। यह समुदाय लंबे अरसे से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। मैतेयी समुदाय की दलील है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद वे लोग राज्य के पर्वतीय इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे। फिलहाल वे लोग मैदानी इलाको में तो जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन पर्वतीय इलाको में जमीन खरीदने का उनको अधिकार नहीं है। आदिवासी समुदाय उसकी इस मांग का विरोध करता रहा है।आदिवासी संगठनों का कहना है कि ऐसा होने पर मैतेयी समुदाय उसकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर लेगा।

इश्तिहार जैसी राजनीति की कहानियां

इसमें थोड़ा फेरबदल कर अगर मोहब्बत की जगह राजनीति करने की गुस्ताखी की जाए, तो आज के माहौल में यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है। मौजूदा दौर की सियासत में ऐसी ही कहानियां चल रही हैं। कहा कुछ जाता है और आशय कुछ और होता है। और जो असल मकसद होता है, वो कभी सीधे शब्दों में बयां ही नहीं किया जाता। शब्दों के इस खिलवाड़ से राजनैतिक बाजियां कैसे पलटी जाती हैं, इसके कुछ उदाहरण हाल ही में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में राकांपा के मुखिया शरद पवार ने पहले इस्तीफा देने का ऐलान किया, जिससे उनके समर्थक भावुक होकर उनसे पद पर बने रहने की अपील करने लगे। राजनीति और दल में उनका क्या ओहदा है, राज्य को उनकी कितनी जरूरत है, इसकी व्याख्याएं की जाने लगीं। राकांपा की बैठकों का दौर चला और शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया गया। और फिर शरद पवार ने अपने समर्थकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस्तीफा वापस ले लिया, अब वे फिर से राकांपा के प्रमुख हैं। श्री पवार के इस कदम से एक तरफ उनकी बटी सुप्रिया सुले का दमबदा बढ़ गया, क्योंकि शरद पवार के बाद पार्टी की कमान उन्हें ही देने की संभावनाएं सबसे अधिक जतलाई जा रही थीं। और दूसरी तरह भतीजे अजीत पवार को यह सख्त संदेश दे

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत



मणिपुर कई बार हिंसा की लपटों में जला। जबकि सरकारें यह दावा करती आ रही हैं कि मणिपुर अब शांत क्षेत्र में बदल गया है। पिछले साल और इस वर्ष राज्य के कई जिलों को अप्सपा कानून के दायरे से बाहर भी कर दिया गया था लेकिन राज्य में हाल ही में हुई हिंसा ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। मणिपुर की हिंसा कोई सामान्य हिंसा नहीं है। एके–47 से फायरिंग से लेकर कई धर्मस्थलों, घरों और वाहनों को आग के हवाले

कर देना छोटी बात नहीं है। उपद्रवियों के हाथों में भारी संख्या में हथियार देखकर प्रथम दृष्टि में यही दिखाई दिया कि वे सत्ता को खुली चुनौती दे रहे हैं। हेरानी की बात तो यह है कि हिंसा में 54 लोगों के मारे जाने का आंकड़ा तीन लेकिन राज्य में हाल ही में हुई हिंसा ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। मणिपुर की हिंसा कोई सामान्य हिंसा नहीं है। एके–47 से फायरिंग से लेकर कई धर्मस्थलों, घरों और वाहनों को आग के हांति

कायम करने के लिए ले जाया गया। विविधता में एकता ही अवधारणा अमूर्त नहीं है। इस एकता को मजबूत करने के लिए शासन व्यवस्था को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। संघर्ष की स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब एक वर्ग महसूस करता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनकी संस्कृति और विशिष्ट पहचान खतरे में है। मणिपुर की हिंसा पहाड़ी और घाटी की पहचान के विभाजन का ही परिणाम है लेकिन इस हिंसा को टाला जा सकता था। दरअसल

चिंतन और योजना, परिश्रम, संकल्प और निरंतरता सफल जीवन के प्रमुख अवयव



की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि विचारों को कभी सुप्त होने या मरने ना दिया जाए। हो सकता है आपके विचार करोड़ों डॉलर के हो । वर्तमान अर्थव्यवस्था में समृद्धि के ईंजन माने जाने वाले सनराइज उद्योग, सॉफ्टवेयर, खाद्य संस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक के विकास के पीछे भी नवप्रवर्तन का हाथ है। इसी के आधार पर नगरों को स्मार्ट नगरों में बदला जा रहा है। नवप्रवर्तन या नवाचार से में सिर्फ मानव जीवन की परेशानियों के न्यूतनतम किया है, बल्कि मानव जीवन को आसान और सुखमय भी बनाया जा रहा है। नवप्रवर्तन और मस्तिष्क की खोज के कारण ही जापान में 6.5 रेक्टर का भूकंप सामान्य माना जाता है,जबकि भारत में यह तबाही ला सकता

है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेनिसिलिन जैसी प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) के अविष्कार ने रोगों की संभावना को कम कर दिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली के भावी विकास को एक गति प्रदान की है। जेनेरिक औषधि, रोबोटिक सर्जरी, जीन एडिटिंग जैसी प्रक्रिया स्वास्थ्य सुधार हेतु एक मजबूत आधार मानी जाती है। सामाजिक विकास आर्थिक समन्वयक और न्याय प्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास नवप्रवर्तन के योगदान से ही आया है। सोशल मीडिया जैसे नवीन प्लेटफार्म ने व्यक्ति की अभिव्यक्ति के अधिकार को स्वतंत्र किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीण से आधुनिक रूपांतरण में कृषी क्षेत्र से भारी उद्योगों पर बल देने में किसानों के देश को सॉफ्टवेयर उद्योग

राज्य के नगा और कुकी यानि आदिवासी समुदाय को यह लगने लगा था कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है और मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग एक सियासी खेल है। आल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर का कहना है घकि मैतेई समुदाय की भाषा संविधान की आठवीं सूची में शामिल है और इनमें से कईयों को अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और आर्थिक रूप से कमजोर (इंडब्ल्यूएस) का फायदा मिल रहा है। आदिवासियों को डर है कि मैतेई समुदाय का सत्ता में पहले से ही वर्चस्व है। अगर मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया गया तो यह पहाड़ी आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षण के दायरे को खत्म कर देगा। आदिवासी नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर घाटी विरोधी भावनाओं को भड़काया। आदिवासी समूहों के विरोध 1 के पीछे राज्य सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ लगातार बढ़ रहा असंतोष भी एक कारण है। सरकार समर्थक समूहों का कहना है कि जनजाति समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री वीरेन घंसिह को सत्ता से हटाना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने ड्रस के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। वीरेन सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध में बेदखली अभियान चलाया था जिसमें मार्च में कुकी समुदाय का एक गांव भी शिकार

प्रयागराज, बुधवार 10 मई, 2023

आज का राशिफल

मेघ :— आज कुछ अच्छे आसारों से मन प्रफुल्लित रहेगा। रोजगार संबंधी यात्रा में अवरोध संभव। शिक्षार्थियों के लिए विशेष लाभ के आसार है। शिक्षा क्षेत्र में जुड़े सभी छात्रों को परिश्रम करने की आवश्यकता है।
बृषभ :— स्वयं पर भरोसा कर योजनाओं को सुचारु रूप से क्रियान्वित करें। संबंधों में सरल व व्यवहारिक बनने की कोशिश करें। आर्थिक चिंता संभव। शिक्षार्थियों के लिए विशेष लाभ के आसार है।
मिथुन :— किसी महत्वपूर्ण कार्य में अवरोध मन को हतोत्साहित करेगा। संबंधों के प्रति नयी शिकायतें संभव। किसी विद्वान के विचारों से प्रभावित मन मे उत्साह का संचार होगा। क्रोध पर नियंत्रणरखें।
कर्क :— कोई नई जिज्ञासा मन को आकर्षित करेगी। भौतिक सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। शिक्षा–प्रतियोगिता के दिशा में प्ररिश्रम तीव्र होगा। रोजगार में प्रगति संभव। कटु शब्दों का ध्यान रखें।
सिंह :— किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। आवेश में लिये गये निर्णय से पश्चाताप संभव। शिक्षा–प्रतियोगिता की दिशा में प्ररिश्रम तीव्र होगा।
कन्या :— समस्याओं के समाधान हेतु मन नए युक्तियों पर केन्द्रित होगा। महत्वपूर्ण कारयेर के प्रति निष्ठा न करे। छोटी–छोटी बातों पर क्रोधित न हो। शिक्षा–प्रतियोगिता के दिशा में प्ररिश्रम तीव्र होगा।

तुला :— मन सकारात्मक विचारों से प्रभावित होगा।। नाजुक संबंधों में सन्तुलित व मधुर वाणी का प्रयोग करें। कोई आपका अपना बिगड़े हुए संबंधों मे सुधार कराएगा। किसी कार्य से संपन्न होने के आसार हैं।
वृश्चिक :— सभी प्रकार के दायित्वों की पूर्ति हेतु सन्तुलित योजना पर चलें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में संबंधों का सहयोग प्राप्त होगा। विरोधियों की प्रबलता से कठिनाइयां संभव। मधुर वाणी का प्रयोग करें।
धनु :— नए समीकरण लाभकारी कार्य क्षमता के परिचायक होंगे। प्रणय सम्बन्ध मे प्रगाढ़ता बढ़ेगी। आय–व्यय मे सन्तुलन बनने का प्रयत्न करें। आलस्य का त्याग करें। रोजगार के अवसर सुलभ होंगे।
मकर :— कोई नई जिज्ञासा मन को आकर्षित करेगी। भौतिक सुख–साधनों की लालसा बढेगी। शिक्षा–प्रतियोगिता के दिशा में प्ररिश्रम तीव्र होगा। रोजगार में प्रगति संभव। कटु शब्दों का ध्यान रखें।
कुंभ :— पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर आप उत्साहित होंगे। नियोजित कार्यकुशलता प्रगति के लिए आशान्वित होंगे। सुखद कारयेर की व्यवस्तता रहेगी। भौतिक सुख–साधनों की लालसा बढेगी।
मीन :— क्षमता से परे किसी कार्य की जिम्मेदारी लेना हानिकार हो सकती है। विद्यार्थी शिक्षा मे लापरवाही ना करें। रोजगार में नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय मुद्दे कोई नहीं उठा रहा

कर्नाटक विधानसभा चुनाव कई मायने में बहुत अनोखा है। उसके अनोखेपन का एक पहलू यह है कि किसी भी पार्टी का नेता राष्ट्रीय मुद्दे नहीं उठा रहा है। यहां तक कि अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर चुनाव लड़ रही भाजपा भी कोई राष्ट्रीय मुद्दा

नहीं उठा रही है। हो सकता है कि कोई भी पार्टी असली मुद्दा नहीं उठा रही है इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे भी सामने नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर असली मुद्दे उठाए गए तो उन पर जवाब देना होगा। दूसरी ओर कांग्रेस को लग रहा है कि अगर असली और राष्ट्रीय मुद्दे उठाए गए तो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को तस्वीर में लाना होगा, जो ठीक नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों पर सब चुप हैं। सवाल है कि राष्ट्रीय मुद्दा क्या है, जिसे कांग्रेस को उठाना चाहिए? सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा मणिपुर का है, जहां आदिवासी और मैती समुदाय के बीच संघर्ष में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, एक सौ से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 14 हजार के करीब लोग घर छोड़ कर भागे हैं। देश के अंदर की बड़े हिस्से में सेना तैनात है और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को नियुक्त किया गया है। पड़ोसी राज्य मेघालय में भी हिंसा हुई है और दिल्ली तक में दोनों समुदाय के छात्रों के बीच टकराव हुआ है। बहुत दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में इसका मुद्दा बना रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को संभाल लिया लेकिन भाजपा से मणिपुर नहीं संभल रहा है।एक असली और राष्ट्रीय मुद्दा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे देश के नामी पहलवानों का है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड़ा पहलवानों को समर्थन देने जंतर मंतर गई थीं। यह राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा बना हुआ है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और कार्रवाई के लिए 15 दिन से ज्यादा से धरने पर बैठी हैं। पर कांग्रेस इसे मुद्दा नहीं बना रही है। कर्नाटक के चुनाव में इसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड़ा ने यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था लेकिन कर्नाटक में यह नारा नहीं दिया जा रहा है।तीसरा बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का है। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के पांच जवान एक साथ शहीद हुए हैं। आतंकवादियों ने आईईडी विस्फोट करके सेना के दस्ते पर हमला किया। एक सैन्य अधिकारी भी घायल हुआ है। आतंकवाद समाप्त कर देने का दावा करने वाली सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन न तो कोई सरकार से जवाब मांग रहा है और न सरकार जवाब दे रही है।



डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रोड़ शो

■ **डिप्टी सीएम ने भाजपा मेयर प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड़ शो**

प्रयाग दर्पण संवाददाता

अयोध्या। चुनाव के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन किया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के रोड़ शो में भगवा धारण किये अपार जनसमूह सड़क पर उतरा। भीषण गर्मी तथा आसमान आ रही गर्म धूप भी पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह को कम नहीं कर सकी। ठोल नगाड़े के साथ रोड़ शो के दौरान हजारों की संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयघोष से परिवेश को गुंजायमान कर दिया। नाका गांधी आश्रम से रिकाबगंज तक निकले दो किमी से लम्बे मार्ग में दर्जनों स्थानों पर लोगो ने रोड़ शो पर पुष्पवर्षा करके स्वागत किया। रथ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के साथ सांसद लल्लू सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, प्रत्याशी महंत गिरीश पति त्रिपाठी शामिल हैं। संचालन महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि यूपी के सभी नगर निगमों पर भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली है। त्रिपल इंजन की सरकार बनाकर



यहां की जनता अयोध्या को कमल की फूल की तरह खिलाकर देगी। रामभक्तों के बीच सपा वाले प्रचार प्रसार करने तक नहीं आये। हम विकास के साथ सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप हर सुविधा प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है। जिसके लिए अयोध्या को योजनाओं की श्रंखलाएं प्रदान

की गयी है। यहां अंतर्राष्ट्रीय सुविध्ा युक्त रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के बेहतर रोड़ कनेक्टिविटी दी जा रही है। क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने कहा कि भाजपा इस चुनाव में एतिहासिक विजय की ओर अग्रसर है। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के पथ पर चलते हुए सबका विश्वास हासिल करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि

तेज धमाका होने से छत उड़ी, दीवार ढही,सात लोग घायल,दो की हालत गंभीर पुलिस ने आसपास के घर खाली कराए

प्रयाग दर्पण संवाददाता कानपुर। शहर में नवाबगंज थानाक्षेत्र के पहलानपुरवा में सोमवार रात 2.30 बजे एक मकान में तेज धमाका हो गया। धमाका से मकान की छत उड़ गई और दीवार भी ढह गई। हादसे में सात लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। आशंका जताई गई कि सिलेंडर या फ्रिज का कंप्रेसर फटा है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच पड़ताल की।आजादनगर इलाके के पहलवानपुरवा निवासी वंशराज का मकान है। जिसमें पहली मंजिल पर विष्णु और सुनील सागर किराए पर रहते हैं। जानकारी के मुताबिक मकान में पहली मंजिल के हिस्से में विष्णु रहता है। उसमें ही विस्फोट हुआ है। धमाका होने से कमरे में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर मौके पर डीसीपी सेंद्रल प्रमोद कुमार,थाना प्रमारी नवाबगंज,फील्ड

सड़क हादसे में अघेड़ की मौत

लखनऊ। थाना मोहनलालगंज क्षेत्र में एक अघेड़ की सड़क हादसे में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। श्यामबाबू पुत्र राजकुमार कोरी निवासी बिन्दीवा थाना मोहनलालगंज ने पुलिस को सूचना दिया कि मंगलवार को सुबह साढ़े नौ बजे उसके पिता राजकुमार व उनका मझला भाई विकास उम्र 19 घर से उसके मामा के गांव फीकर खेड़ा बाइक से जा रहे थे। ग्राम कुडा गांव बाजार थाना मोहनलालगंज के पास पावर टेक ट्रैक्टर जिस पर पालेसर बंधा था से चालक द्वारा लापरवाही से चलाते हुए उनके बाइक में टक्कर मार दी। जिससे उसके पिता गंभीर रूप से घायल गए। उपचार के लिए सीएचसी मोहनलालगंज ले जाया गया। जहां चिकित्सकों द्वारा उनके पिता राजकुमार उम्र 52 पुत्र सीताराम निवासी बिन्दीवा को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

वाह री सरकार जमकर हुआ भ्रष्टाचार, प्रधान और अधिकारियों ने किया बंदरबांट

पहला (सीतापुर)। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला की ग्राम पंचायत सैर में विकास के लिए भेजे गए धन का सही उपयोग प्रधानों व सचिवों ने नहीं किया। गांव के लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा गांव में निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए तो पूरा मामला खुलकर सामने आ जायेगा। गांव का विकास हो, गांव के लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर परेशान न होना पड़े। इसके लिए ग्राम पंचायतों को धन दिया गया और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन गांव के लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधान व सचिव ऐसे लोगों को लाभ दे रहे हैं, जो उनके करीबी है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल रहा है और गांव में कराये गये कार्यों की निष्पक्ष जांच

गरीबों के चेहरे पर खुशी का भाव लाना सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है। भाजपा प्रत्याशी महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि विकास की रश्मि से प्रकाशित अयोध्या आने वाले समय में देश के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में एक होगी। इसका सबसे ज्यादा लाभ अयोध्या की जनता को मिलने वाला है। इस अवसर पर जिला प्रमारी पदमसेन चौधरी, क्षेत्रीय महामंत्री त्रयम्बक तिवारी, सहाकारी बैंक के सभापति धर्मेन्द्र प्रताप सिंह टिल्लू, अवधेश पाण्डेय बादल, डा बांके बिहारी मणि त्रिपाठी, कमलेश श्रीवास्तव, अक्ेश श्रीवास्तव, आलोक कुमार सिंह रोहित, हरिश श्रीवास्तव, अभय सिंह, गिरीश पाण्डेय डिपुल, जितेन्द्र दूबे मिंदू प्रधान, नीरज कन्नौजिया, इंरणवीर सिंह, सत्य प्रकाश वर्मा, डा अवधेश वर्मा, बालकृष्ण वैश्य, आलोक द्विवेदी, रवि सोनकर, सुनील तिवारी शास्त्री, विकास सिंह, अमल गुप्ता, तिलक राम मौर्या, शैलेन्द्र कोरी, परमानंद मिश्रा, राजू सिंह, राकेश मणि त्रिपाठी, विशाल सिंह बाबा, सूरज सोनकर, रवि शर्मा, ज्ञान केसरवानी, नीरज जायसवाल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता, समाजिक संगठनों से जुड़े लोग उपस्थित रहे।



यूनित व बम डिस्पोजल स्व्वाइड भी मौके पर पहुंचा। पुलिस को विष्णु के कमरे में रखी एक लोहे की अलमारी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मिली है। फोरेंसिक टीम ने यहां से सैपल भी लिए हैं।दीवार ढहने से पता चला कि हमारे घर में विस्फोट हुआ मकान मालिक वशंराज ने बताया,जिस वक्त विस्फोट हुआ, उस वक्त हम सभी सो रहे थे। अचानक तेज आवाज सुनी तो कुछ समझ नहीं आया। धमाके से मकान

ग्रामीण इलाकों में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कराएं एफआईआर

रायबरेली।जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने कहा कि अभियान चलाकर जिन घरों में अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं हुआ है, उन परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया जाए। बिजली चोरी तथा बिजली का अनुचित उपयोग एक सामाजिक बुराई है, इसे दूर करना सभी का दायित्व है। उन्होंने निर्देश दिये कि बिजली का बिल हर महीने उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के अनुपयुक्त उपयोग एवं गड़बड़ी करने वाले के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराकर समुचित कार्यवाही की जायेगी। बचत भवन सभागार में जनपद के समस्त घरों में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु आयोजित बैठक में डीएम माला श्रीवास्तव ने कहा कि मृतकों के नाम पर चल रहे बिजली कनेक्शन तथा अवैध बिजली कनेक्शन के विरुद्ध भी शीघ्र ही अभियान चला कर बिजली चोरी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करते हुए जुर्माना भी लगाया जायेगा। कटिया लगाने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देश दिये कि गर्मियों के दिनों में विद्युत दुर्घटनाएं रोकने के समुचित प्रयास किये जाएं। विद्युत उपभोक्ताओं के बीच भी जागरूकता अभियान चलाया जाये कि केबिल कटा न हो, खुले तार आदि न हो। विद्युत उपकरणों को विशेष रूप से, नंगे पैर न छुआ जाये। उन्होंने कहा कि घरों में अर्थिग अवश्य कराई जाए, यह प्रत्येक विद्युत कनेक्शन के साथ अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने बैठक में र्विेष योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित एजेंसी को निर्देश दिये कि वे लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास करें।बैठक में एडीएम एफआर पूजा मिश्रा,अधीक्षण अभियंता प्रथम यदुनाथ राम,अधीक्षण अभियंता द्वितीय रामकुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

वाह री सरकार जमकर हुआ भ्रष्टाचार, प्रधान और अधिकारियों ने किया बंदरबांट



कराने की मांग उठाई जा रही है। ग्रामीणों द्वारा गुप्तघर बातों में चर्चा की जा रही है कि गांव में प्रधान सचिव ने खूब धन का बन्दरबांट किया है और प्रधान गांव में झांकने तक नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि योजनाओं से वंचित रह गए लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सुविधा शुल्क लिए जाने की शिकायत भी करी है। उनके विकासखंड के ग्राम पंचायत सैर के प्रान तथा सचिव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप ग्रामीणों ने लगाए गए हैं। गांव

महिला ने सर्राफा व्यापारी को चप्पल से पीटा,बचाने आई पत्नी से भी की मारपीट

पाली,हरदोई। पाली कस्बे की सर्राफा मार्केट में एक दबंग महिला ने सर्राफा कारोबारी को चप्पल से पीट दिया। पति को बचाने आई उसकी पत्नी को भी दबंग महिला ने पीटा है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।वायरल वीडियो की जानकारी करने पर पता चला कि पाली कस्बे की सर्राफा बाजार में निक्की रस्तोगी की सर्राफा की दुकान है। सोमवार शाम को उनकी दुकान पर मोहल्ला काजी सराय निवासी एक महिला आई हुई थी, बताया गया कि लेन देन को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। जिसके बाद दबंग महिला ने सर्राफा कारोबारी निक्की रस्तोगी की चप्पल से पिटाई कर दी। बचाने आई उसकी पत्नी से भी दबंग महिला ने मारपीट की। पूरी घटना सर्राफा कारोबारी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित दंपति ने पाली थाने में महिला के विरुद्ध तहरीर दी है। वहीं आरोपी महिला के पति ने बताया है कि निक्की रस्तोगी पर उनके 12 लाख रुपए हैं।

एकेटीयू की टीम गुजरात पहुंची, योजनाओं की ली जानकारी तीन दिवसीय दौरे पर एकेटीयू इनोवेशन हब की टीम

प्रयाग दर्पण संवाददाता लखनऊ। प्रदेश में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एकेटीयू ने अपना प्रयास तेज कर दिया है। जिसमें इनोवशन और स्टार्टअप को गति देने के लिए डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की इनोवेशन हब की टीम तीन दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी के एक्सपर्ट और सीईओ प्रो. तुषार रावल से मुलाकात करने पर उन्होंने स्टार्टअप नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान की।

कुलपति प्रो आलोक कुमार राय और प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा सुभाष चंद शर्मा के निर्देशन और डॉ. अनुज शर्मा की अगुवाई में टीम मंगलवार पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनक्व्यूबेशन सेंटर और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी पहुंची।

यहां टीम ने उद्यमिता और नवाचार के लिए किए जा रहे कार्यों को समझा और अधिकारियों से उनके अनुभव को भी जाना। वहीं प्रो. रावल ने टीम को बताया कि गुजरात में उद्यमिता और नवाचार के लिए ऐसी नीति बनाई गई है। जिससे कि युवा अपनी सृजन क्षमता को

ट्रक की टक्कर से बेटी की मौत,पिता घायल

रायबरेली।पुत्री को स्कूल छोड़ने जा रहे पिता की बाइक को एक तेज रफतार ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे मासूम की मौत हो गई है, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हुआ है ।हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क मार्ग जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों और क्षेत्रीय विधायक ने इसी तरह समझा-बुझाकर लोगों को शांत किया है। यह हादसा सलोन परशदेपुर मार्ग पर हुआ है। क्षेत्र के गांव पूरे बंधन का पुर्वा निवासी दयाशंकर मंगलवार की सुइक अपनी बेटी आरुषि (7 वर्ष) को बाइक से लेकर टिकरिया गाँव स्थित एक निजी विद्यालय में पढ़ने के लिए छोड़ने जा रहे थे । रास्ते में सलोन की तरफ से आ रहे एक तेज रफतार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी । जिससे मासूम सड़क पर गिर गई ,और ट्रक ने उसे कुचल दिया। जिसके कारण उसकी मौके पर मौत हो गई। इस हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को खड़ा कर कर मौके से भाग गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया ।

सपा-भाजपा का रोड़ शो टकराया,अखिलेश बिफरे,टकराव होते-होते बचा

सपा प्रमुख के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी-योगी जिंदाबाद के लगाए नारे

प्रयाग दर्पण संवाददाता कानपुर। कानपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रोड़ शो किया। इस दौरान उन्होंने सपा की महापौर प्रत्याशी वंदना बाजपेई के समर्थन में वोट मांगे। अखिलेश यादव के रोड़ से कुछ ही दूरी पर बीजेपी से महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडेय संग भाजपा के पार्षद प्रत्याशी का भी जुलूस निकल रहा था। उनके साथ विधानसभा अध् यक्ष सतीश महाना भी मौजूद थे। कानपुर देहात में जनसभा को खत्म करने के बाद अखिलेश यादव दोपहर 3 बजे कानपुर पहुंचें। यूपी निकाय चुनाव के अंतिम और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है। मंगलवार को चुनाव प्रचार का शोर खत्म होने से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव का रोड़ शो फूलबाग से होकर सड़क हादसों में 5 लोग

घायल, 3 गम्भीर, जिला

अस्पताल रेफर

सिधौली (सीतापुर) । अलग- अलग सड़क हादसों में 5 लोग घायल हो गये। जिसमें से 3 को गम्भीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हरिश्चंद्र पुत्र रमेश निवासी रायगंज अपने ससुर ओमकार पुत्र श्रीकृष्ण व साले अमन 18 पुत्र ओमकार निवासीगण गढ़ीखेरवा थाना संदना रिस्तेदार की शादी समारोह से वापस आये थे और किसी कार्य से तीनों कही जा रहे थे तभी गांव के कुछ दूरी पर ही सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। जिससे तीनों घायल हो गये। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर को पकड़ कर पुलिस को सूचित किया और घायलों को सीएचसी सिधौली एम्बुलेंस बुलाकर भेजा। सीएचसी से हरिश्चंद्र और ओमकार को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इसी प्रकार समित पुत्र अयोध्या निवासी मानपर अपनी मामी श्रीमती पत्नी पप्पू निवासी धनाखेरा जिला हरदोई को लेकर मोटरसाइकिल से सोमवार की रात नौ बजे के करीब सिधौली संदना थाना में नदवन गांव से सिधौली की ओर आ रहे थे।



स्टार्टअप और नवाचार के जरिए सतत विकास के लक्ष्य ने अपना योगदान दे सकें। साथ ही आत्मनिर्भर गुजरात बनाने में भूमिका निभाए। डॉ धर्मेद्र और जय जोशी ने भी टीम को उद्यमिता और नवाचार के बारे में बताया। इसके बाद टीम औद्योगिक उपायुक्त के कार्यालय भी पहुंची। जहां संयुक्त आयुक्त उद्योग

ठाकुरगंज में युवक और मलिहाबाद में महिला फांसी पर झूली

लखनऊ। राजधानी में इन दिनों खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे है। सोमवार को तीन युवकों के फांसी लगाये जाने की घटना को चौबीस घंटे नहीं बीते कि मंगलवार को दो और मामले सामने आ गये। थाना ठाकुरगंज में युवक और मलिहाबाद में महिला ने फांसी लगाकर जाना दे दी। दोनों में खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं होने के कारण पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है।पहली थाना ठाकुरगंज की है। श्रीमती शर्मा पत्नी शेर खां निवासिनी कल्यानमल बेनीगंज जनपद हरदोई हाल पता किराये का मकान न्यू फरीदीपुर सरकारी स्कूल के पास ने सूचना दिया कि मंगलवार की सुबह वह अपने कमरे में सो रही थी कि लोगों का शोर सुनकर नीचे आकर देखा तो उसके देवर शाहरूख उम्र 18 गेट में रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। मृतक अविवाहित था।

सूचना पर एसआई परवेज अंसारी ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। परवेज अंसारी के अनुसार खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दूसरी घटना थाना मलिहाबाद की है। मान सिंह पुत्र हरिश्चंकर यादव निवासी ग्राम रायपुर राजा थाना लखनऊ ने सूचना दिया कि मंगलवार को दोपहर समय करीब एक बजे उसे सूचना मिली कि उसकी बहन वंदना यादव उम्र32 पत्नी सुधर लाल उर्फ सुधार यादव पुत्र सूरज यादव निवासी माधोपुर थाना मलिहाबाद की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर वह अपने परिजनों के साथ जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन वंदना का शव छत के पंखे में साड़ी के फंदा में लटका हुआ है। जानकारी मिलते ही एसआई प्रवंश कुमार भी मौके पर पहुंच गए। उनके द्वारा बताया गया कि मृतका का विवाह करीब 11 वर्ष पूर्व हुआ था। मृतका के तीन बच्चे हैं और पति खेती का कार्य करता है। इसी की खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

सपा-भाजपा का रोड़ शो टकराया,अखिलेश बिफरे,टकराव होते-होते बचा



घंटाघर के लिए रवाना हुआ। अखिलेश के रोड़ शो के दौरान ही भाजपा के जुलूस का नेतृत्व सतीश महाना कर रहे थे। सतीश महाना का रोड़ शो करीब 70 मीटर आगे चल रहा था,वहीं सपा प्रमुख का कफिला ठीक उनके का झंडा लिए कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के सामने आने से पहले ही टकराव न हो पुलिस सतर्क हो गई। एक जगह पुलिस ने

शुरू कर दिए।

पति ने पत्नी पर किया चाकू से जानलेवा हमला,मचा हड़कंप

रायबरेली।मंगलवार को दीवानी न्यायालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब पारिवारिक विवाद में पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। न्यायालय परिसर में महिला पर हुए हमले के बाद भगदड़ मच गई। पुलिस ने हमलावर पति को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि महिला को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।कड़ी सुरक्षा वाली दीवानी कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा कर दिया। पति के हमले से गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहाँ उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार रंभा का पुर्वा थाना ऊंचाहार की रहने वाली उमा सिंह का अपने पति दुखहरन सिंह से पारिवारिक विवाद न्यायालय में चल रहा है। उमा सिंह मंगलवार को इसी विवाद में पेशी पर आई थी। वह न्यायालय परिसर स्थित अभियुक्त लॉकअप के पास अपने वकील के चेंबर में बैठी थी , उसी समय उसके पति दुख हरण सिंह ने महिला पर चाकू से हमला बोल दिया। हमले में महिला के पेट में दो गंभीर घाव हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। पीड़िता के वकील सनोज यादव ने बताया कि उमा सिंह की 22 साल पहले नसीरबाद थाना क्षेत्र तिवारी पुर के रहने वाले दुखहरन सिंह से हुई थी। दोनो के तीन बच्चे है। दुखहरन सिंह कमाई के लिए विदेश गया और जब वापस लौटा तो उसका व्यवहार बदल गया। वो आये दिन अपनी पत्नी को पीटने लगा।पति की पिटाई से परेशान पत्नी ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। जिसका मुकदमा लंबित है ।

